बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 81 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 06 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए 7 जगह लगेगी लोक अदालत, 1.80 लाख लोगों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली।नई दिल्ली। दिल्ली में यातायात के लंबित चालान के निपटारे के लिए 10 जनवरी को दिल्ली सात जिला अदालतों में लोक अदालत का आयोजन होगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण व दिल्ली यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित लोक अदालत में 1.80 लाख चालान का निपटारा किया जाना है। चालान के लिए सोमवार से नोटिस व चालान दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसमें 30 नवंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए समझौता योग्य चालान ही इस लोक अदालत में सुनवाई में रखे जा सकेंगे। पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट में यह लोक अदालत लेगी।

दिल्ली विधानसभा सत्र : प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में हंगामा, आप के 4 विधायकों पर एक्शन, 3 दिन के लिए निष्कासित

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में ही एलजी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विधायकों ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा किया। इस हंगामे के कारण स्पीकर को कार्रवाई करनी पड़ी और विपक्ष के विधायकों को सदन से बाहर निकलवाना पड़ा। हंगामा करने के चलते आप विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को अगले 3 दिन के लिए सदन कि कार्यवाही से निष्कासित कर दिया गया है। विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी वायु प्रदूषण के मुद्दे पर भारतीय भाजपा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, और इसी के चलते सदन में आप के विधायक मास्क लगाकर पहुंचे। यह शीतकालीन सत्र 8 जनवरी तक चलेगा, हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबासाहब अम्बेडकर के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक निर्णय लिए हैं। इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यवसायिक प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने पिछले 10 महीनों में दिल्ली में बहुत काम किया है। कई पुरानी समस्याएं हैं जिनका सरकार सामना कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में नतीजे दिखेंगे। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, यमुना नदी की सफाई की समस्या है, और सड़कों की समस्या है जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। इन सभी चीजों में समय लगता है। सरकार तत्परता से काम कर रही है।

भाजपा प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो दूर बात करने को भी तैयार नहीं

आम आदमी पार्टी ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने कहा, दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, वे ज़हरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो दूर बात करने को भी तैयार नहीं है। आज हमें विधानसभा से क्यों निकाला गया? क्योंकि हमने मास्क पहने थे। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा एक्यूआई मॉनिटर पर पानी डालने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। यह शर्मनाक है। कैग रिपोर्ट पर उन्होंने कहा, भाजपा पहले दिल्ली में जो लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं उसपर जवाब दे। सभी डेटा दिखाते हैं कि इस साल प्रदूषण सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार के डेटा से पता चलता है कि पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही है, तो प्रदूषण कहां से आ रहा है?।

लोग सांस नहीं ले पा रहे, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? - आतिशी

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने कहा, चार महीने से दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे, बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों की जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? एक्यूआई मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है। ग्रैप सही तरीके नहीं लगा रही। आज दिल्ली वालों को सांस लेने के लिए ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं। आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भाजपा का भंडाफोड़ करने के लिए आप के सभी विधायक ये मास्क पहन कर आए हैं।

यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है - मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अभिनंदन करते हुए, मैं कहना चाहूंगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। विधानसभा का यह सत्र पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया गया है, जहां महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं।

खासकर प्रदूषण जैसे मुद्दों पर, जिन पर सरकार ने सभी को चर्चा के लिए बुलाया है, सभी विधायकों को बहस में हिस्सा लेना चाहिए और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके हर पल का इस्तेमाल दिल्ली की भलाई के लिए करें। भाजपा नेता करनैल सिंह ने आप विधायकों द्वारा मास्क पहनकर के प्रदर्शन पर कहा, वे मास्क लगाकर सदन को ये बताने गए थे कि उन्होंने 11 साल में दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार किया है। कितना प्रदूषण फैलाया है। संविधान के अनुसार जब उपराज्यपाल का संबोधन होता है तो उसको कोई बाधित नहीं करता लेकिन उन्होंने एक-एक करके उपराज्यपाल के भाषण को भी बाधित करने की कोशिश की।

मास्क पहनकर आप नेताओं ने किया प्रदर्शन

विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायक मुंह पर मास्क लगाकर प्रदर्शन करते नजर आए। सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा करने पर स्पीकर के निर्देश पर आप विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, जरनैल सिंह और सोमदत्त को बाहर कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने परिसर में विरोध जताया। इसके साथ ही एक अन्य प्रस्ताव के तहत उन्होंने एलजी के अभिभाषण में विघ्न डालने वाले आप विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की मांग की जिसे स्वीकार कर लिया गया और सदन की कार्यवाही कल दोपहर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

गजनी को धार्मिक उन्मादी नहीं, केवल..., नेहरू और वामपंथी इतिहासकारों पर भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली । सोमनाथ मंदिर के पहले विध्वंस के एक हजार वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा ने कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों पर इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है।

पार्टी का कहना है कि इस दिन को केवल याद करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए भी देखा जाना चाहिए कि किस तरह महमूद गजनी को एक साधारण लुटेरे के रूप में दिखाया गया और उसके धार्मिक उद्देश्य को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास को इस तरह पेश किया, जिससे महमूद गजनी को धार्मिक उन्मादी नहीं, बल्कि केवल धन कमाने वाला शासक बताया गया। भाजपा का आरोप है कि इससे देश की पहचान और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि उस समय सोमनाथ मंदिर के पुजारियों और तत्कालीन राजा ने महमूद गजनी से शिवलिंग को न तोड़ने की अपील की थी। बदले में लाखों सोने के सिक्के देने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन महमूद गजनी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वह व्यापार करने वाले व्यक्ति के बजाय मूर्तिभंजक के रूप में जाना चाहता है।

वामपंथी सोच पर उठाए सवाल

भाजपा नेता ने कहा कि महमूद गजनी के साथ आए एक इतिहासकार ने इस पूरी घटना का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। उनके मुताबिक, यह तथ्य वामपंथी इतिहासकारों की उन सभी थ्योरियों को खारिज करता है, जिनमें कहा गया कि गजनी का उद्देश्य केवल धन लूटना था, न कि धार्मिक विध्वंस।

नेहरू की किताब पर आरोप

त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' किताब में जवाहरलाल नेहरू ने महमूद गजनी को आस्था से अधिक योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने लिखा था कि गजनी धर्म के नाम का इस्तेमाल केवल विजय और खजाने के लिए करता था।

भाजपा का कहना है कि यही सोच बाद में इतिहास की किताबों में दोहराई गई और सच को दबा दिया गया।

पहचान और सम्मान की बात

भाजपा के अनुसार, यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि यह समझा जा सके कि भारत के इतिहास और आत्मसम्मान के साथ किस तरह भद्दा मजाक किया गया। पार्टी का कहना है कि अब समय आ गया है कि इतिहास को सही तथ्यों के साथ देश के सामने रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच्चाई जान सकें।

दिल्लीवासियों को प्रदूषण से मिली हल्की राहत, खराब श्रेणी में पहुंची फिजा

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में रविवार की तुलना में आज कुछ सुधार देखा गया है। जहां रविवार को यह बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था, वहीं सोमवार को इसमें गिरावट दर्ज की गई और यह खराब श्रेणी में आ गया है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार, सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह गिरावट प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर नियंत्रण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, हालांकि अभी भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में एक्यूआई की स्थिति पर नजर डालें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के अलीपुर में 275, आनंद विहार में 320, अशोक विहार में 301, आया नगर में 178, बवाना में 195, बुराड़ी में 216, और चांदनी चौक इलाके में 337 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं, डीटीयू इलाके में 272, द्वारका सेक्टर-8 में 288, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 में 153, आईटीओ में 253, जहांगीरपुरी में 316, लोधी रोड में 182, मुंडका में 281, नजफगढ़ में 232, नरेला में 284, पंजाबी बाग में 276, आरकेपुरम में 295, रोहिणी में 299, सोनिया विहार में 296, विवेक विहार में 318, और वजीरपुर में 308 एक्यूआई दर्ज किया गया है। यदि हवा साफ है तो उसे इंडेक्स में 0 से 50 के बीच दर्शाया जाता है। वायु गुणवत्ता के संतोषजनक होने की स्थिति तब होती है जब सूचकांक 51 से 100 के बीच होती है। 101-200 का मतलब वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी का है, जबकि 201 से 300 की बीच की स्थिति वायु गुणवत्ता की खराब और 301 से 400 के बीच का अर्थ वायु गुणवत्ता की बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। 401 से 500 की श्रेणी में वायु की गुणवत्ता गंभीर बन जाती है। ऐसी स्थिति में इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचता है। पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह जानलेवा है।

जबरन गले लगना और तारीफ नहीं आई काम, ट्रंप के बयान को लेकर जयराम रमेश का मोदी सरकार पर तंज

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर दिए गए एक हालिया बयान के मद्देनजर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वॉशिंगटन नई दिल्ली पर बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकता है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि नमस्ते ट्रंप, ह्यूडी मोदी कार्यक्रम, जबरन गले मिलना और अमेरिकी नेता की प्रशंसा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट से कोई खास फायदा नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप, ह्यूडी मोदी के कार्यक्रम, वे सभी (जबरदस्ती के) गले मिलना और अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रशंसा करने वाले वे सभी सोशल मीडिया पोस्ट बहुत कम कारगर साबित हुए हैं। ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, वे (भारत) मुझे खुश करना चाहते थे। मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं; वे नेक दिल हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मुझे खुश करना उनके लिए जरूरी था। वे रूस से व्यापार करते हैं और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यह उनके लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप की ये टिप्पणी तब आई जब एयर फोर्स वन में उनके साथ यात्रा कर रहे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ ही वह मुख्य वजह है जिसके चलते नई दिल्ली अब रूस से काफी कम तेल खरीद रही है। ग्राहम ने अपने टैरिफ बिल के बारे में बात की, जिसका उद्देश्य रूसी तेल खरीदने वाले देशों से आयात पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाना है। ग्राहम ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ग्राहकों पर दबाव डालना होगा। जानते हैं कि वह भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीद से खुश नहीं हैं और वाशिंगटन नई दिल्ली पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकता है। कांग्रेस ने ट्रंप के इसी बयान मोदी सरकार पर सियासी हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त भारत के प्रति अपना कभी नरम, कभी सख्त रवैया जारी रखे हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो वे अमेरिका से आयात होने वाले तेल पर टैरिफ बढ़ा देंगे। जयराम रमेश ने कहा, वे सभी नमस्ते

ऑपरेशन सिंदूर से सशस्त्र बलों ने दुनिया के सामने भारत की दृढ़ता का प्रदर्शन किया : राधाकृष्णन

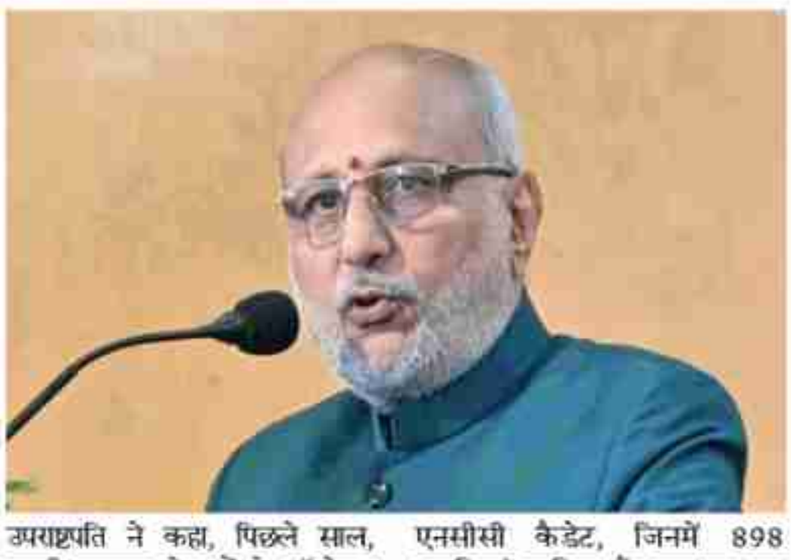

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि सशस्त्र बलों ने पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत को गौरवान्वित किया। दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में अपने संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि बलों ने सैन्य कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए दुनिया के सामने देश के संकल्प और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अभियान के दौरान एनसीसी के प्रशंसनीय योगदान की भी सराहना की। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी ने सराहनीय योगदान दिया, जब लगभग 72,000 एनसीसी कैडेट नागरिक सुरक्षा उपायों के लिए स्वेच्छा से सेवाएं देकर 'एनसीसी योद्धा बन गए। अधिकारियों के अनुसार, इन कैडेटों ने आपातकालीन अभ्यास, रक्तदान शिविरों और नागरिक सुरक्षा से संबंधित अन्य गतिविधियों में सहायता की। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सात मई, 2025 की सुबह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। उपराष्ट्रपति ने कहा, पिछले साल, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दुनिया में भारत के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की राष्ट्र के सम्मान, संप्रभुता और उसके नागरिकों की रक्षा करने की अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक था। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सोमवार को एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जिसका समापन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा। देश भर से कुल 2,406 एनसीसी कैडेट, जिनमें 898 लड़कियां शामिल हैं, लगभग एक महीने तक चलने वाले इस शिविर में भाग ले रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कैडेटों को केवल गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाला नहीं, बल्कि एक नए भारत का राजदूत बताया, जो 2047 तक एक 'आत्मनिर्भर और मजबूत भारत, एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा, आप में से प्रत्येक में मुझे एक विकसित भारत की मजबूत नींव दिखाई देती है, एक विकसित, समावेशी और आत्मविश्वासी देश की नींव दिखाई देती है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति क़ानून और वैश्विक शांति पर प्रभाव

वैश्विक स्तरपर सारी दुनियाँ हैरान रह गई जब 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सल्यूट रेसोल्व के नाम से एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। इसके तहत अमेरिकी वायुसेना और विशेष बलों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलीया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया गया।जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में अमेरिका द्वारा एक तेजी से आगे बढ़ी सैन्य कार्रवाई की गई, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि अमेरिका ने वेनेजुएला में हवाई हमलों और विशेष ऑपरेशन के ज़रिए मादुरो को हिरासत में लिया और उन्हें विदेश ले लाया गया।अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि मादुरो पर नार्को- आतंकवाद, कोकीन तस्करी, साजिश और अमेरिका के खिलाफ हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप हैं,जिनके कारण वह अमेरिकी न्याय के सामने खड़ा होगा। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि इन्हीं अभियोगों के आधार पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होगी।यह आरोप अमेरिका के अंतर्गत जारी अभियोगों पर आधारित है, जिनमें दावा किया जाता है कि मादुरो की सरकार और सहयोगी अमेरिकी हितों और कानूनों के खिलाफ भारी मात्रा में अवैध गतिविधियों में संलग्न थे।हालांकि मादुरो और उनके समर्थक इन आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि वैश्विक स्तरपर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया विषय नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच राजनीतिक,आर्थिक और सामरिक तनाव रहा है जिसमें मुख्य रूप से तेल संसाधनों, असंतुलित द्विपक्षीय संबंधों और मतभेद शामिल हैं।1976 में वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग को राष्ट्रीयकृत किया था,जिससे अमेरिकीकंपनियों का नियंत्रण खत्म हो गया था जिस पर अमेरिका ने लंबे समय तक आपत्ति जताई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कड़वी टकर और भी तीव्र होती गई। साथियों बात अगर हम इस कार्रवाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सफल सैन्य ऑपरेशन बताया है इसको समझने की करें तो, उन्होंने वेनेजुएला में ड्रग तस्करी और नार्को-आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब अस्थायी रूप से वेनेजुएला के सरकारी कार्यों को संभालेगा और देश को सुरक्षित, व्यवस्थित और न्यायपूर्ण संक्रमण की ओर ले जाएगा।उनके खिलाफ नार्को- टेररिज्म,कोकीन की तस्करी और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें न्यूयॉर्क के संघीय न्यायालय में ट्रायल का सामना करने का इरादा बताया गया है।अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उन अभियोगों के आधार पर है जो मादुरो पर भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद समर्थित गतिविधियों के लिए लगाए गए हैं।

वहीं मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों ने इस ऑपरेशन को अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है क्योंकि यह बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के एक संप्रभुत राष्ट्र के खिलाफ सशस्त्र हमला है। साथियों बात अगर हम हमले के बाद विश्व के प्रमुख देशों की प्रतिक्रियाओं को समझने की करें तो, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? इस वैश्विक घटना पर रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों ने तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की हैये देश अमेरिकी कार्रवाई को वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन, क्षेत्रीय अखंडता का भंग और एक शक्तिवादी आक्रमण बताते हुए निंदा कर रहे हैं। रूस ने अमेरिका की इस हरकत को अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है। ईरान और क्यूबा ने भी संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा करने और शांति स्थापित करने की अपील की है।वहीं यूरोपीय संघ ने स्थितिमें कुछ अलग रुख अपनाया उन्होंने सीधे निंदा नहीं की, बल्कि तथ्यों की पुष्टि और तथ्यों के प्रकाश में निर्णय लेने की बात कही,यह कहते हुए कि वे अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान करते हैं।जिसका व्यापक अर्थ यह है कि ईयू ने खुलकर अमेरिका का समर्थन नहीं किया, लेकिन स्पष्ट निंदा भी नहीं की। कुछ देशों ने इस संकट को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का विषय बनाया है, तकरीबन सभी प्रमुख वैश्विक शक्तियाँ इस घटना को अंतरराष्ट्रीय कानून की बड़ी परीक्षा के रूप में देख रही हैं।साथियों बात अगर हम तेल और ड्रग्स विवाद की पृष्ठभूमि को समझने की करें तो अमेरिका का कहना यह है कि वेनेजुएला दुनियाँ के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक का घर है और यह देश नशीले पदार्थों और अपराध नेटवर्क के लिए एक मुख्य केंद्र बन गया है,इसलिए इस कार्रवाई को उसने नशीले पदार्थों का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षित रखने की आवश्यक कार्रवाई बताया है। परन्तु आलोचक इसे तेल संसाधनों पर नियंत्रण पाने की एक अर्थव्यवस्थाकि रणनीति के रूप में भी देखते हैं। वे तर्क देते हैं कि इस हमले के पीछे आर्थिक हितों की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि वेनेजुएला के तेल भंडारों के कारण यह क्षेत्र आर्थिक और सामरिक रणनीति के केंद्र में पहुंच गया है। साथियों बात अगर हम मानवाधिकार और वैधता के सवाल के दृष्टिकोण से समझने की करें तो, कई मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि अमेरिका बिना स्पष्ट और पारदर्शिता के निर्दोष नागरिकों और नेताओं को निशाना बना रहा है, और यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ हो सकती है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि एक देश दूसरे देश पर बिना सुरक्षा परिषद की अनुमति के प्रस्तुत खतरे के जवाब में बल का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह विवाद अब अंतरराष्ट्रीय अदालतों, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शांति संरचनाओं के लिए एक बड़ा परीक्षण बन गया है। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय कानून और सार्वभौमिक संप्रभुता के दृष्टिकोण से इस मुद्दे को समझने की करें तो,किसी देश के सिटिंग राष्ट्रपति-समेत किसी राष्ट्राध्यक्ष को एक अन्य देश के सशस्त्र बलों द्वारा पकड़कर विदेश लाना,अंतरराष्ट्रीय कानून सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का जटिल उल्लंघन हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 2(4) के अनुसार, किसी अन्य देश के खिलाफ बल प्रयोग केवल स्वयं रक्षा या सुरक्षा परिषद की अनुमति के तहत ही किया जा सकता है।अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को नार्को-आतंक कारणों, मादुरो पर अभियोग और सुरक्षा हितों के आधार पर उचित ठहराया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्याय विशेषज्ञ यह कहते हैं कि किसी अन्य देश के उच्चतम नागरिक नेता के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और हिरासत लेना सीधे तौर पर संप्रभुता का उल्लंघन और बल प्रयोग का उदाहरण है, जब तक कि यह सीधे तौर पर खुद अमेरिका के विरुद्ध सीधा हथियारबंद हमला न रहा हो। कई विशेषज्ञों ने इसे अपराधी आक्रमण तक कहा है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है।

संप्रभुता का उल्लंघन तब अधिक गहरा हो जाता है जब उस देश की संसद या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी नहीं ली जाती,जैसा इस मामले में स्पष्ट नहीं दिख रहा है।अंतरराष्ट्रीय कानून के मानदंडों के अनुसार, वर्चस्ववादी शक्तियों के इस तरह के हस्तक्षेप से वैश्विक आदेश और मानक प्रभावित होते हैं, जिससे भविष्य में अन्य नियमित रूप से चुने गए नेताओं पर भी इसी तरह के दावों के आधार पर कार्रवाई का परिपेक्ष्य बन सकता है। साथियों बात अगर हम, यह वैश्विक लोक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन है या नहीं? इसको समझने की करें तो, यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका के इस कदम से वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन होता है? इस विवाद का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि इसमें राजनीतिक वैचारिकता, शक्ति- राजनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सिद्धांतों का मिश्रण है।एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थक देश यह तर्क देते हैं कि मादुरो जैसे नेता ने अपनी सरकार के भीतर तख्तापलट, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन की नीतियों को लागू किया है। अमेरिकी प्रशासन इसे अपराध नियंत्रण और लोकतंत्र स्थापना के रूप में पेश कर रहा है। दूसरी ओर,ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक और कई देशों के सरकारी बयान बताते हैं कि ऐसा सैन्य हस्तक्षेप अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है, क्योंकि इसने किसी देश की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, चुनावों और निरंकुश संप्रभुता को दरकिनार किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है, यह कहते हुए कि अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान और संप्रभुता का आदर करना ही वैश्विक व्यवस्था का आधार है,इसलिए, यह कहना अधिक सटीक होगा कि अमेरिका का यह कदम वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौतीपूर्ण परिदृश्य बन गया है। भले ही इसे कुछ राजनीतिक तर्क दिए जाएं।

साथियों बात अगर हम क्या 'तीसरा विश्व युद्ध' शुरू होने वाला है? इस प्रश्न को समझने की करें तो, जहाँ एक ओर यह घटनाक्रम वैश्विक सत्ता संतुलन में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, वहीं विशेषज्ञों की राय में अभी तक तीसरे विश्व युद्ध जैसी कोई निश्चित शुरुआत नहीं हुई है। एक तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत तभी मान्य होगी जब दो या दो से अधिक परमाणु-सक्षम रणनीतिक धड़े एक दूसरे के विरुद्ध व्यापक सैन्य गठबंधन, आर्थिक ब्लॉकों और वैश्विक स्तर पर जारी संघर्ष में जुड़ें,जो इस समय का वास्तविक परिदृश्य नहीं है।हालांकि रूस, ईरान, क्यूबा और चीन जैसे देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और यह कहा है कि यह वैश्विक शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकता है, वैश्विक युद्ध के जोखिमों पर बहस तेज हुई है। जिन देशों ने आलोचना की है, वे यह मानते हैं कि अगर दुनियाँ की प्रमुख शक्तियाँ एक दूसरे के खिलाफ सैन्य गठबंधनों और प्रतियोगिताओं हिंसा की ओर बढ़ें, तो एक बड़े पैमाने पर संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है।फिर भी, वैश्विक नेताओं के लिए तीसरा विश्व युद्ध की घोषणा किसी भी तरह से आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। इस विषय पर विशेषज्ञ अभी आगे की अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं और संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाइयों का इंतजार कर रहे हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह घटना न सिर्फ दक्षिण अमेरिका या अमेरिका का विषय है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति समीकरण, अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता तथा वैश्विक सुरक्षा संरचनाओं की परीक्षा भी है।अमेरिका का तर्क है कि यह कार्रवाई नार्को-टेररिज्म और सुरक्षा कारणों से आवश्यक थी,कई देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून उल्लंघन घोषित किया है।संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक शक्तियाँ, क्षेत्रीय समूह और न्यायविद इस पर गहरा विश्लेषण कर रहे हैं।यह संघर्ष समय का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं में से एक है और इसके परिणाम दशकों तक वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक रणनीति पर प्रभाव डाल सकते है।

सम्पादकीय...

हैरतंगेज मिशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांतिदूत वाली अपनी छवि बनाने की कोशिश तो बहुत की। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समेत आठ युद्ध रुकवाने का दावा किया और खुद को शांति का मसीहा बताया। यहां तक कि नोबेल शांति पुरस्कार पर दावा भी जता दिया लेकिन उन्होंने नववर्ष के तीसरे ही दिन वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। ऐसा करके ट्रंप ने दुनिया में अशांति फैला दी है। यह अमेरिकी सेना का हैरतंगेज मिशन था जिसमें उसका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ यह एक संप्रभु देश के खिलाफ ताकत का घोर इस्तेमाल और अमेरिका की अधिपत्यवादी कार्रवाई है। अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है और शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाला एक्शन है। वेनेजुएला पर हमले को लेकर दुनिया बंटी हुई है। संयुक्त राष्ट्र एक मृत संस्था है, उसकी सुनेगा कौन? ट्रंप ने दादागिरी करके न केवल लैटिन अमेरिकी देशों को बल्कि चीन और रूस को भी दिखा दिया है कि अगर कोई भी देश उसकी खींची गई लक्ष्मण रेखा पर नहीं चलेगा तो वहां तख्तापलट करवा दिया जाएगा। वैसे ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में विदेशी धरती पर कुल 622 बम गिरा चुके हैं। सीरिया, नाइजीरिया, ईरान, सोमालिया, यमन और ईराक पर अमेरिका बम गिरा चुका है। ट्रंप के इशारे पर ही बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक सरकार का मुखिया बनाकर अपनी कठपुतली बनाया है। ऐसा ही वेनेजुएला में करना चाहता है। वेनेजुएला पर कहानी के पीछे खेल कुछ और है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है जिसे 303 अरब बैरल से भी ज्यादा बताया जाता है। कई प्रतिबंधों की वजह से यह अब तक अनछुआ भंडार है। इसके अलावा उसके पास सोने और गैस का भी जबर्दस्त भंडार है। यूं तो वेनेजुएला की ओर से इन पदार्थों का निर्यात न के बराबर है लेकिन अगर अमेरिका की इस तक पहुंच होती है तो ट्रंप प्रशासन को मध्य पूर्व (भारत के पश्चिम एशिया) में तेल की खरीद पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह सीधे वेनेजुएला के तेल भंडार का दोहन करके अपने ऊर्जा बाजार को आगे बढ़ा सकता है और अपने तेल रिजर्व को सुरक्षित भी रख सकता है। इसके अलावा वेनेजुएला में बीते वर्षों में जिस तरह से भू -राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, वह भी अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। दरअसल, वेनेजुएला के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने के बाद से चीन और रूस ने वेनेजुएला से रिश्ते बढ़ाए हैं और उसे अरबों डॉलर की सहायता मुहैया कराई है। कई बार यह सहायता वेनेजुएला के तेल के लिए ही की गई है। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने रूस, चीन, ईरान और क्यूबा से हथियार और सुरक्षा के लिए कई उपकरण भी हासिल किए हैं। ऐसे में ट्रंप सरकार वेनेजुएला पर दबाव बनाकर एक बार फिर पूरे दक्षिण अमेरिका में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में है। निकोलस मादुरो तब से ट्रंप की आंखों में खटक रहे थे जब से उन्होंने अमेरिकी तेल कम्पनियों की सम्पत्ति जब्त की थी। अमेरिका आरोप लगाता रहा है कि वेनेजुएला की सरकार ?अमेरिका के लिए खतरा है। मादुरो ड्रग्स कार्टेल चलाते हैं और खतरनाक ड्रग्स की तस्करी अमेरिका भी की जाती है। ट्रंप का यह भी आरोप है कि मादुरो की नीतियों से लाखों वेनेजुएलाई नागरिक देश छोड़ अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अमेरिका पिछले कुछ दिनों से कथित रूप से ड्रग्स ले जाने वाली नावों को निशाना बना रहा था लेकिन नार्कोटिक विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला तो ड्रग्स तस्करी का बहुत छोटा खिलाड़ी है। यह सही है कि मादुरो की सत्ता अवैध है लेकिन यह उसका आंतरिक मामला है। ट्रंप का असली मकसद तो तेल का खेल है। ऐसे विध्वंसक खेल अमेरिका पहले भी खेलता आया है लेकिन जब हम थोड़ा इतिहास पलटते हैं, तब हमें कुछ और ही कहानी दिखती है। वियतनाम वॉर में हजारों बेगुनाह मारे गए। अफगानिस्तान में 20 साल युद्ध चला। अफगान नागरिक आज भी उसका दंश झेल रहे हैं। एक झूठी खुफिया जानकारी के आधार पर इराक को तबाह कर दिया गया। इसी वजह से इस्लामिक स्टेट पैदा हुआ। हवाई हमलों में मासूम बच्चों की हत्याएं हुईं। मगर इन सबके सूत्रधार अमेरिका पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उंगली तक नहीं उठाई। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वॉरंट नहीं निकाला। मसलन, मार्च 2003 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यु बुश ने इराक पर हमले का आदेश दिया था। कहना ये कि सद्दाम हुसैन के पास वैपंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। यानी, भयानक बर्बादी पैदा करने वाले हथियार। इसी को आधार बनाकर अमेरिका ने सेना उतारी। सद्दाम को अरेस्ट कर फांसी पर लटकाया और फिर कहा कि कैमिकल वैपन की बात भ्रामक थी। हमें इराक में ऐसा कोई हथियार नहीं मिला। अमेरिका ने लीबिया में घुसकर कर्नल गद्दाफी को मारकर तख्तापलट किया था। जिस देश में भी अमेरिका घुसा वे सभी तबाह होकर रह गए। एक तरफ से अमेरिका ने वेनेजुएला को हड़प लिया है। ट्रंप वहां भी ऐसे नेता को सत्ता में लाकर कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं जो उनके इशारों पर चले। न्यूयार्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वार बताया है। अमेरिका के विपक्षी दल और कमला हैरिस ने भी अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया है। ट्रंप ने मादुरो पर मुकदमा चलाने और सजा देने की बात कही है। इस मौके पर यह नहीं कहा जा सकता कि विश्व इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा क्योंकि इजराइल-हमास युद्ध और रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दुनिया बंटी हुई है। बड़े-बड़े देश बयानबाजी तो बहुत करते हैं लेकिन बड़ी ताकतों के सामने कोई किसी देश का साथ नहीं देता। फिलिस्तीन और यूक्रेन के उदाहरण हमारे सामने हैं।

जिस की लाठी उसकी भैंस इसी मुहावरे को प्रमाणित करती हुई दुनिया चल रही है। चीन, रूस और ब्राजील वेनेजुएला की कितनी मदद करते हैं यह देखना होगा। दुनियाभर के देशों को सतर्क होकर अपनी लाठी को

(पाकिस्तान) में भी भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ चिह्न

पड़ोस में बिखरे पड़े हैं हमारे स्वर्णिम अतीत के बहुमूल्य पन्ने। भगवान राम के युवराज पुत्र लव ने जिस शहर को बसाया था, वह शहर लाहौर है। लाहौर के शाही किले में अब भी महाराजा लव की स्मृतियों को कांपते अधरों से स्मरण करता लव-मंदिर मौजूद है, मगर धीरे-धीरे हमारी विरासत का वह सुनहरी पृष्ठ भी भुरभुराने लगा है। लाहौर के शाही किले की चारदीवारी में आलमगीरी-गेट के पास स्थित है यह मंदिर, जहां अतीत के कुछ दुर्लभ चिह्न एवं कुछ पिंडियां मौजूद हैं। पाकिस्तानी शासन तंत्र का स्थापत्य विभाग इस पुराने खजाने का महत्व अब समझता है, संभवत इसीलिए इसके रख-रखाव पर अब ध्यान दिया जा रहा है।

आतंकवाद एवं धार्मिक उन्माद के कैंसर से ग्रसित इस पड़ोसी देश में हमारी विरासत बची रहे, इतना भी कम नहीं। अब इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि इस शहर की स्थापना मां सीता और श्रीराम के पुत्र राजकुमार लव ने की थी। एक अन्य चर्चित शहर कसूर की स्थापना उसके जुड़वां भाई राजकुमार कुश ने की थी। इस शहर में हजारों साल पुराने लव मंदिर की सफाई व कारसेवा और साथ ही एक शिवालय का निर्माण सर गंगाराम ने कराया था। भूख और तंगहाली से जूझते पाकिस्तानियों को अब भगवान राम और उनके बेटे लव की याद आ रही है। पाकिस्तानियों के अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन ने कई लोगों को अचरज में डाल दिया है। भारत में पहले भी इस तरह की बात कही जाती रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। मुस्लिम लीग समर्थित अखबार 'द डॉन' की एक रिपोर्ट में लाहौर शहर के प्राचीन इतिहास की पड़ताल की गई है। इस रिपोर्ट में माना गया है लाहौर को राजकुमार लव ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस शहर को यह नाम मिला। साथ ही पाकिस्तानी शहर 'कसूर' को भगवान राम के दूसरे बेटे कुश का बसाया हुआ बताया गया है। इसके अलावा भी इस शहर के कई पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताया गया है।

आमतौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया वहां के प्राचीन हिन्दू इतिहास से इनकार करता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पाकिस्तान में ज्यादा बात नहीं की जाती। वे मुहम्मद बिन कासिम से पहले के इतिहास को 'अंधेरे का युग' कहते रहे हैं। लाहौर किले के भीतर मौजूद लव मंदिर लाहौर की सबसे पुरानी इमारत है। यह मंदिर किले के बनने से काफी पहले से वहां मौजूद था। मुगल काल में बादशाह अकबर ने इसी के चारों ओर किले का निर्माण करा दिया। इसके बाद यह मंदिर भी किले का हिस्सा हो गया, लेकिन मंदिर के डिजाइन और मौजूदा शहर की सतह से इसकी उसकी ऊंचाई के आधार पर माना गया है कि यह मंदिर किले की अपेक्षा काफी पुराना है।

लाहौर किले में मंदिर के नीचे खुदाई की गई, जिसमें उसके प्राचीन होने के सबूत मिले। 7वीं सदी में चीनी यात्री युवान चांग भारत की यात्रा पर आया था। इस दौरान वह लाहौर भी गया। उसने लाहौर के बारे में लिखा कि यह शहर सुंदर और बड़े मंदिरों और बागों से भरा हुआ है। इसके अलावा वर्ष 1982 में लिखे गए एक दस्तावेज में भी लाहौर के मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। ये लिखित दस्तावेज आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। टिब्बी बाजार भी लाहौर का भीड़भाड़ वाला इलाका है। इसी इलाके के बीचोंबीच एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसे टिब्बी वाला शिवालय कहा जाता है। ये शिवालय अरब आक्रमण के पहले से लाहौर में मौजूद है। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लाहौर शहर लगभग 4000 हजार साल पुराना है। अरब आक्रमण से पूर्व यहां कई बड़े हिंदू और बौद्ध शासक हुए थे। मुझे वर्ष 1988 में कटासराज-यात्रा के मध्य वहां के पंजाब विश्वविद्यालय में जाने का अवसर मिला था। संस्कृत-हिंदी व 'पाली' की अमूल्य पांडुलिपियां पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित हैं। वहां अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं की कुल बाइस हजार पांडुलिपियां रखी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी संस्कृत विभाग के एक शोध छात्र राजेश सरकार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। कुल मिलाकर लाहौर सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लाहौर में हिंदू, सिख, जैन संस्कृति के अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें आर्य समाज मंदिर, महादेव मंदिर, शीतला मंदिर, भैरव मंदिर, रावर रोड पर श्रीकृष्ण मंदिर, अकबरी मंदिर, दूधवाली माता मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह की समाधि, डेरा साहिब, जैन दिगंबर मंदिर व भाबड़िया, जैन श्वेतांबर मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। मगर हम इनकी व्यवस्थित जानकारी एक समग्र ग्रंथ के रूप में पिरो नहीं पाए। और अब तक्षशिला (पाकिस्तान) में भी भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ चिह्न मिले हैं। इसी तक्षशिला की गत सप्ताह हुई खुदाई में कुषाण काल के सिक्के व आभूषण एवं हिन्दू-मूर्तियों के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं।

खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून को ठेंगा दिखाने वालों को बड़ा झटका लगा है

उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों- उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम पर इस मामले में एक साल तक जमानत याचिका दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने हालांकि इस मामले में अन्य आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। पीठ ने कहा, ''अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ताओं- उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में वैधानिक कसौटी लागू होती है। कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।'' अदालत ने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली है, उनकी भूमिका सीमित और परिस्थितिजन्य मानी गई है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम पर दंगों की साजिश रचने, भीड़ को भड़काने और सुनियोजित तरीके से हिंसा को दिशा देने के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखा जाये तो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला केवल दो व्यक्तियों की जमानत याचिका का निपटारा नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय संकल्प का स्पष्ट संदेश है। उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोग कोई साधारण आरोपी नहीं हैं। ये वे चेहरे हैं जिन्होंने विचारधारा की आड़ में सड़कों पर आग लगाने की मानसिकता को खाद पानी दिया। यह बार बार साबित हो चुका है कि दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़के थे। उनके पीछे शब्दों के बारूद, भाषणों की चिंगारी और योजनाबद्ध उकसावे की लंबी तैयारी थी। ऐसे मामलों में यदि अदालत नरमी दिखाती, तो यह न केवल न्याय के साथ अन्याय होता बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक संकेत भी जाता। अदालत ने सही कहा कि इन दोनों की स्थिति अन्य आरोपियों से अलग है। यह अंतर केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। दंगा केवल पत्थर फेंकने से नहीं होता, दंगा उस सोच से पैदा होता है जो समाज को बांटने का काम करती है। जब किसी मंच से यह कहा जाए कि सड़कों पर उतर कर व्यवस्था को जाम कर दो, तब वही शब्द बाद में आग बन जाते हैं। जमानत खारिज करने का फैसला उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं। यह फैसला बताता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। मुकदमे में देरी को लेकर अदालत की टिप्पणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वर्षों से एक तर्क गढ़ लिया गया था कि अगर मुकदमा लंबा चल रहा है, तो आरोपी को स्वतः राहत मिलनी चाहिए। यह सोच न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है। अगर गंभीर साजिशों में केवल समय के आधार पर जमानत मिलने लगे, तो हर देश विरोधी ताकत समय को हथियार बना लेगी।

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नए-नए मुद्दे

चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास कर रहे सरमा ने दावा किया है कि 2011 में 34 फीसदी आबादी मुस्लिम थी, जो अब लगभग 40 फीसदी हो गई है। उनका दावा है कि इसमें जयादा हिस्सा बांग्लादेश से आए मियां मुस्लिम' का है। उनके खिलाफ बाकी लोगों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और इसलिए यह सभ्यताओं का संघर्ष है। हैरानी की बात है कि असम में पिछले 10 साल से भाजपा की ही सरकार है। पांच साल से तो खुद सरमा मुखमंत्री हैं और 11 साल से जयादा समय से केंद्र में भाजपा की सरकार है। फिर सीमा पार से कैसे घुसपैठ हो रही है और कैसे मियां मुस्लिम' आबादी इतनी जयादा बढ़ती जा रही है?

अनिल जैन

आमतौर पर चुनावों को पानीपत की लड़ाई बताया जाता है लेकिन अब एक राज्य के चुनाव को सभ्यताओं का संघर्ष बताया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को सभ्यताओं का संघर्ष कहा है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास कर रहे सरमा ने दावा किया है कि 2011 में 34 फीसदी आबादी मुस्लिम थी, जो अब लगभग 40 फीसदी हो गई है। उनका दावा है कि इसमें जयादा हिस्सा बांग्लादेश से आए मियां मुस्लिम' का है। उनके खिलाफ बाकी लोगों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और इसलिए यह सभ्यताओं का संघर्ष है। हैरानी की बात है कि असम में पिछले 10 साल से भाजपा की ही सरकार है। पांच साल से तो खुद सरमा मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से जयादा समय से केंद्र में भाजपा की सरकार है। फिर सीमा पार से कैसे घुसपैठ हो रही है और कैसे मियां मुस्लिम' आबादी इतनी जयादा बढ़ती जा रही है? इससे पहले वे मदरसे बंद कराने से लेकर बहुविवाह रोकने सहित कई उपाय आजमा चुके हैं। अब जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और सरकार के विरोध का माहौल बन रहा है, वैसे-वैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नए-नए मुद्दे उछाले जाने लगे हैं। गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती से तैयारी कर रही है। इस बार कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है। सो, ध्रुवीकरण कराना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए सभ्यताओं के संघर्ष का शिगूफा उछाला जा रहा है।

बांग्लादेश की घटनाओं का असर बंगाल में

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है और पश्चिम बंगाल में उन हिंदुओं की जाति बता कर राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 18 दिसंबर को जिस हिंदू युवक की हत्या की गई थी और पेड़ पर लटका कर जिंदा जला दिया गया था वह दलित था। उनका कहना है कि दलित हिंदू की हत्या हुई इसलिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ सवाल नहीं उठा रही हैं। दूसरे हिंदू अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या का मुद्दा भी जोर-शोर से उठ रहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर कूटनीतिक पहल कर रही है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुला कर दो बार इस बारे में चिंता जताई गई है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी अपनी ओर से कोलकाता में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास में गए और हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताई। कोलकाता से लेकर सिलिगुड़ी तक भाजपा और अन्य हिंदू संगठनों के प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच सिलिगुड़ी और दार्जिलिंग में बांग्लादेशियों का बहिष्कार शुरू हो गया है। सिलिगुड़ी होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने बांग्लादेशी नागरिकों को अपने होटल में नहीं ठहराने का फैसला किया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। अगर उस समय तक हिंसा होती है और हिंदू शिकार बनते हैं तो बांग्लादेश और मुसलमानों के प्रति नाराजगी बढ़ेगी। इससे हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं। इसीलिए भाजपा बांग्लादेश के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

अब कांग्रेस और डीएमके में भी खटपट

कांग्रेस के नेता पता नहीं किस सोच में हर जगह पहले से बने हुए समीकरण और राजनीतिक संरचना को ध्वस्त करना चाहते हैं। बिहार में उन्होंने ऐसा किया, जिसका नुकसान सभी पार्टियों को हुआ। उसके बाद कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश को लेकर बयानबाजी करने लगे। उधर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन टूट ही गया। अब तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता हाथ आजमा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसे सरकार में शामिल किया जाए। कांग्रेस को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए क्योंकि उसके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का भी अपना घोषणापत्र है और जनता से किया गया वादा है, जिसे पूरा करने के लिए उसका सरकार में रहना जरूरी है। कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे से पहले इसकी मांग शुरू कर दी है।

कांग्रेस के तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने कहा है कि अगले चुनाव से पहले डीएमके को ऐलान करना चाहिए कि कांग्रेस सरकार का हिस्सा बनेगी तभी तालमेल की घोषणा होगी। दूसरी ओर डीएमके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को अगर सरकार में शामिल करने का ऐलान किया गया तो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस की दूसरी पार्टियां भी इसकी मांग करेंगी और फिर जो खिचड़ी सरकार बनेगी उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगी। दोनों तरफ से इस पर जोर आजमाइश चल रही है। इस बीच कांग्रेस के नेता सरकार के कर्ज के आंकड़े निकाल कर स्टालिन सरकार को कठघरे में खड़ा करने लगे हैं।

ओडिशा में जनता की ताकत दिखी

ओडिशा की भाजपा सरकार ने पिछले दिनों बड़ा फैसला किया था। विधानसभा में विधेयक लाकर सरकार ने विधायकों के वेतन को तीन गुना से ज्यादा बढ़ा दिया था। पहले विधायकों का वेतन और भत्ता एक लाख रुपए के करीब था, जिसे बढ़ा कर 3.35 लाख रुपया कर दिया गया। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों की पेंशन में भी लगभग तीन गुना बढ़ोतरी कर दी गई। इसे लेकर बड़ा विवाद हुआ, सवाल उठे। कहा गया कि विधायकों का वेतन और भत्ता बढ़ना चाहिए क्योंकि कई बरसों से नवीन पटनायक की सरकार ने उसमें बढ़ोतरी नहीं की थी। लेकिन ओडिशा जैसे गरीब राज्य में एक बार में वेतन तीन गुना से ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। आम लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। सोशल मीडिया में इसके खिलाफ नैरेटिव बना। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने तुरंत इस जनभावना को पकड़ा और ऐलान कर दिया कि वे बढ़ा हुआ वेतन नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो उनके वेतन का बढ़ा हुआ हिस्सा जन कल्याण की किसी दूसरी योजना में इस्तेमाल करे। जब बीजू जनता दल के सबसे बड़े नेता ने बढ़ा हुआ वेतन लेने से इनकार कर दिया तो फिर उनकी पार्टी के दूसरे विधायक भी इसके खिलाफ खड़े हुए। अंत में भाजपा के विधायकों को भी मजबूरी में इसका विरोध करना पड़ा। तब भाजपा की सरकार मजबूर हुई बढ़ा हुआ वेतन वापस करने के लिए। बढ़ाए गए वेतन में से जनता के दबाव में कुछ कटौती होगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार पाठी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैनलबना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार पाठी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00863)

अटल स्मृति सम्मेलन में बही काव्य की बयार

मुरादाबाद।

भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के आवाहन पर महापौर विनोद अग्रवाल के नेतृत्व में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर सोमवार को अटल स्मृति सम्मेलन (नगर निगम स्तर) टाउन हॉल स्थित नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल रहे। सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर चर्चा कर उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई इसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अटल स्मृति सम्मेलन में महानगर के प्रसिद्ध व वरिष्ठ साहित्यकारों और कवियों ने अपनी काव्य पंक्ति और रचनाओं के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जिसमें कवियत्री

प्रेमवती उपाध्याय,वरिष्ठ साहित्यकार डा मनोज रस्तौगी,अशोक विश्नोई, श्रीकृष्ण शुक्ल,युवा गीतकार मयंक शर्मा,कवि दुष्यंत बाबा, राजीव प्रखर,डा.मनोज कुमार, समाजसेवी धवल दीक्षित ने काव्य पाठ और रचना पाठ किए। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि अटल जी की नीति में दूरदृष्टि,नेतृत्व में सेवा भाव और निर्णयों में राजनीतिक कुशलता थी। उनका विराट व्यक्तित्व पूरे देशवासियों को नई प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने सभी से अटल जी के व्यक्तित्व पर चर्चा कर आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। सूर्य प्रकाश पाल ने आगे कहा कि भारत द्वारा अपना पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में सफलतापूर्वक किया गया, लेकिन यह परीक्षण दुनिया की नज़र में परमाणु तकनीकी को हासिल करने की दिशा में भारत का पहला कदम था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में 11 से 13 मई 1998 में सफलतापूर्वक किया और इस परीक्षण के बाद भारत एक परमाणु हथियार राज्य के रूप में उभरा।

दिव्यांगोत्थान श्री राम सेवा ट्रस्ट न्यास व शिवसेना द्वारा कंबल वितरण का हुआ आयोजन

परोपकार करना मानव का सबसे बड़ा धर्म - रूचि अभिषेक तिवारी

मेजा प्रयागराज ।

मेजा में ठंड से बचाव के लिए गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण का कार्य समाजसेवियों द्वारा तेजी के साथ किया जा रहा है।मेजा क्षेत्र के जेवनिया गांव में रविवार, 4 जनवरी 2026 को एक कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्यांगोत्थान श्रीराम सेवा ट्रस्ट न्यास, प्रयागराज और शिवसेना के संयुक्त सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में गरीबों, असहायों और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर महाधिवक्ता एम. सी.चतुर्वेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर रुचि अभिषेक तिवारी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि रुचि तिवारी पिछले 11 वर्षों से लगातार ठंड से बचाने के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांट रही हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि रुचि अभिषेक तिवारी हर साल ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटती हैं। वह आधी रात को भी शहर की सड़कों पर फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की सुध लेने निकलती हैं और उन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबलों का वितरण करती हैं । रुचि अभिषेक तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि मानव का सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। उन्होंने अपनों की सेवा को हर नागरिक का कर्तव्य बताया और इस क्षेत्र तथा यहां के लोगों से अपने गहरे जुड़ाव का उल्लेख किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉ. अशोक हरिवंश भैया जी ने रुचि तिवारी के कार्यों को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज के हर व्यक्ति को इसमें सहयोग करना चाहिए। यह कंबल वितरण समारोह जेवनिया (शम्भू का पुरा), पुलिस चौकी के पास संपन्न हुआ।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम

मुरादाबाद।

विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी तिथि वार समय सारणी के अनुसार 6 जनवरी 2026 को मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची के आलेख्य के प्रकाशन के साथ ही 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी इसी प्रकार 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण का कार्य किया जाएगा तथा अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को होना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी नामित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारणी एवं प्रत्येक प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नामित किए गए अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी दशा में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयबद्ध प्रक्रिया है इसमें लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा कहा कि पूर्वाहन 10 बजे से सांय 5 बजे तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाए साथ ही दैनिक निस्तारण की स्थिति को भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। नोटिस जारी होने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा जिसमें व्यक्ति को निस्तारण के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। नोटिस बीएलओ के माध्यम से तामीला कराए जाएंगे। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के साथ-साथ नए मतदाताओं से प्रारूप 6 और संशोधन एवं शिफ्टेड मतदाताओं से प्रारूप 8 भी प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। 11 जनवरी को 11 बजे से 5 बजे तक प्रत्येक बीएलओ द्वारा मतदान केंद्र पर मतदाता सूची पढ़कर सुनाई जाएगी, इस संबंध में भी आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम, एसडीएम सदर राम मोहन मीणा और 'वाइंट मजिस्ट्रेट आदित्य श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

मुरादाबाद शैली की रामलीला को अयोध्या में मिला सर्वश्रेष्ठ सम्मान

मुरादाबाद। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के तत्वाधान में सुरभि रामलीला कला केंद्र ट्रस्ट मुरादाबाद ने तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में रामलीला का मंचन 21 दिसंबर से 03 जनवरी तक किया। इस लीला मंचन को मुरादाबाद शैली की सर्वश्रेष्ठ रामलीला का पुरस्कार मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के कोषाध्यक्ष एस.के. माझी औरआरती दुबे के द्वारा दिया गया। इस अवसर पर हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के पुजारी भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि मुरादाबाद शैली की लीला का मंचन संस्था द्वारा बहुत ही अछे व आधुनिक ढंग से किया गया इस अवसर पर सुरभि रामलीला के निर्देशक संजय सोनी को अंग वस्त्र, श्रीफल व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया इस रामलीला मंचन से मुरादाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे मुरादाबाद शैली की रामलीला की खूब प्रशंसा की गई उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि व अन्य राज्यों में मुरादाबाद शैली की रामलीला की धूम मचाने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रामलीला मंचन के अवसर मिलने की संभावनाएं व्यक्त की गई। 25 सदस्य टीम ने अछी वेशभूषा अछी मंच सज्जा के साथ मंचन में सहभागिता की अयोध्या में रामलीला मंचन के सुखद अनुभव को कलाकारों ने खूब सराहा इस अवसर पर सभी कलाकारों को संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल की बैठक में हुए कई निर्णय

फतेहपुर।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला इकाई की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष बृजेश सोनी के आवास में आयोजित हुई। बैठक में व्यापारियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बृजेश सोनी ने बताया कि आगामी 8 जनवरी को लखनऊ में प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की बैठक होना है, जिसमें जिले से एक सैकड़ा व्यापारियों की सहभागिता होना सुनिश्चित किया गया है। लखनऊ प्रतिभाग के संबंध में सभी विधानसभाओं का दो दिवसीय सघन दौरा किया जाना है। साथ ही फतेहपुर व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर जिले के पीड़ित पटाखा व्यापारियों की पीड़ा से अवगत करायेगा। जिला प्रभारी संजय गुप्ता ने बताया कि व्यापार मंडल द्वारा शीघ्र ही जनपद के सभी कस्बों में बृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाकर सभी स्तर के अधिक से अधिक व्यापारियों को संगठन से जोड़ा जाएगा। जिससे जनपद के सभी व्यापारियों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।

व्यापार मंडल के जिला संरक्षक विनोद गुप्ता ने बताया कि उनका व्यापार मंडल सभी छोटे और बड़े व्यापारियों का सम्मान करता है और उनकी प्रत्येक समस्या के लिए संघर्ष करता है। कहा कि जनपद के भ्रष्ट अधिकारियों की एक सूची बना ली गई है जिसे वह आगामी 8 तारीख को लखनऊ में होने वाली प्रदेश स्तरीय मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल को सौंपेंगे। जिले के किसी भी व्यापारी का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से रजन गुप्ता, कुलदीप सिंह भदौरिया, संजय सिंह जौहरी, मो0 आसिफ एडवोकेट, विनोद सिंह चंदेल, हिमांशु श्रीवास्तव, धीरज बाल्मीकि, शिवम तिवारी, उमेश मौर्य एडवोकेट, मो0 समी खां, अनीस, मो0 अलीम, प्रिंस गुप्ता, मोहम्मद मुकीम, शिवम तिवारी, मोनू गुप्ता, गाजी अब्दुर रहमान गनी, रामबाबू, देवा सिंह आदि व्यापारी उपस्थित रहे।

8 जनवरी की बैठक में लखनऊ जायेंगे एक सैकड़ा व्यापारी

राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात

जिले के पटाखा व्यापारियों की पीड़ा से करायेंगे अवगत

सदस्यता अभियान के जरिये सभी व्यापारियों को संगठन से जोड़ने का करेंगे काम

जीजेयू मुरादाबाद ने परीक्षा कार्यक्रम किया घोषित

मुरादाबाद।

गुरु जम्भेश्वर विश्व विद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। स्नातक की परीक्षाएं बारह जनवरी से तथा परास्नातक की परीक्षायें 15 जनवरी से शुरु होगी। स्नातक परीक्षाएं 11 फरवरी तक तथा परास्नातक परीक्षायें 03 फरवरी तक संचालित होगी।

कुलपति ने बताया कि नकल विहीन परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिये पूर्ण प्रयास किये जायेंगे। प्रथम सेमीस्टर कार्यक्रम घोषित होने के साथ साथ परीक्षा नियन्त्रक द्वारा तैयारियां तेजी से प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी के अनुसार इस विश्वविद्यालय के बैनर तले पहली परीक्षा हो रही है। समस्त प्राचार्यों एवं शिक्षकों से आग्रह है कि वह पूर्ण सहयोग करें। एक विश्व विद्यालय को आदर्श विश्व विद्यालय के रूप में प्रोत्साहित करें। कुल सचिव गिरीश कुमार द्विवेदी एवं परीक्षा नियन्त्रक तथा वित्त नियंत्रक का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है।

दिल्ली के भूजल में यूरेनियम का जहर, किडनी और नर्वस सिस्टम को कर देगा तबाह; सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली में पीने के पानी को लेकर एक गंभीर और चौंकाने वाला खतरा सामने आया है। राजधानी के कई इलाकों के भूजल में सुरक्षित सीमा से अधिक यूरेनियम पाए जाने से न सिर्फ किडनी और हड्डियों पर, बल्कि सीधे दिमाग, नर्वस सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही है और बिना किसी तात्कालिक लक्षण के लाखों लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे दिल्ली एक 'साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी' की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लिए गए 103 भूजल नमूनों में से 13 नमूनों यानी 12.63 प्रतिशत में यूरेनियम की मात्रा तय सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक पाई गई है। इसका अर्थ यह है कि हर आठ में से लगभग एक नमूना दूषित है। उत्तरी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के साथ-साथ रोहिणी, बवाना औद्योगिक क्षेत्र और नांगलोई-नजफगढ़ जैसे इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक यूरेनियम युक्त पानी का सेवन केवल किडनी या हड्डियों तक सीमित नुकसान नहीं करता, बल्कि यह पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इससे दिमागी कार्यक्षमता, याददाश्त, एकाग्रता और मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ता है। समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो इसके दीर्घकालिक परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। यूरेनियम को 'साइलेंट किलर' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में धीरे-धीरे जमा होता है और शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण नजर नहीं आते। एम्स के इंटरनल मेडिसिन विभाग के डॉ. हर्षल आर. साल्वे के अनुसार, यूरेनियम से होने वाली न्यूरोटॉक्सिसिटी तंत्रिका-तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, जिससे याददाश्त कमजोर होती है, सीखने की क्षमता घटती है और मूड डिसऑर्डर की समस्या बढ़ती है। शरीर में जमा यूरेनियम नर्व सिग्नलिंग को बाधित करता है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल मानकों के अनुसार, पानी में यूरेनियम की सुरक्षित सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर (30 पीपीबी) तय की गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में यह मात्रा 59 पीपीबी तक दर्ज की गई, जबकि 13 नमूनों में यूरेनियम 30 पीपीबी से अधिक पाया गया।

यूरेनियम युक्त पानी का असर विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। इससे एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, नींद में गड़बड़ी और मानसिक थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दिल्ली में प्रतिदिन करीब एक हजार करोड़ लीटर पानी की खपत होती है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड लगभग 900 करोड़ लीटर की आपूर्ति कर पाता है। इसमें 10 से 13 प्रतिशत हिस्सा भूजल का है। जिन इलाकों में भूजल दूषित है, वहां यह अदृश्य जहर लोगों के स्वास्थ्य को लगातार प्रभावित कर रहा है। एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. अनंत मोहन बताते हैं कि यूरेनियम सबसे पहले किडनी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका गहरा असर दिमागी कार्यप्रणाली पर पड़ता है। लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन ब्रेन सेल्स की कार्यक्षमता को धीमा कर देता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि प्रभावित इलाकों में आरओ आधारित जल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए, बच्चों को विशेष रूप से ऐसे पानी से दूर रखा जाए, भूजल की नियमित निगरानी हो और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर वैकल्पिक जल स्रोत उपलब्ध कराए जाएं।

रूसी तेल पर दबाव- ट्रंप की चेतावनी, भारत पर बढ़ सकता है अमेरिकी टैरिफ

(वेबवार्ता)

नई दिल्ली। वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति के दबावों के बीच अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर एक बार फिर सख्त संकेत सामने आए हैं। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर लगाम नहीं लगाई, तो अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ बढ़ा सकता है। बता दें कि एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्हें यह मालूम था कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की नीति से खुश नहीं हैं। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि व्यापार के मामले में अमेरिका बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ाने की स्थिति में है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। गौरतलब है कि पिछले साल अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। इनमें से करीब 25 प्रतिशत टैरिफ सीधे तौर पर रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए थे। मौजूद जानकारी के अनुसार, अमेरिका भारत पर यह दबाव इसलिए बना रहा है ताकि रूस की ऊर्जा आय को सीमित किया जा सके। ट्रंप के बयान का असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। सोमवार को आईटी शेयरों पर दबाव दिखा और निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब छह प्रतिशत गिरकर एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। निवेशकों को आशंका है कि अगर व्यापार तनाव बढ़ता है, तो भारत-अमेरिका ट्रेड डील और ज्यादा लटक सकती है। इस बीच रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, ने कहा कि रूस की तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों और भारत पर ऊंचे टैरिफ का असर पड़ा है और भारत ने रूसी तेल की खरीद कुछ हद तक कम की है। उन्होंने ऐसे देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया जो अब भी रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं।

हालांकि व्यापार विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत पहले ही 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है और रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद न होने से वह एक रणनीतिक असमंजस की स्थिति में है। उनके मुताबिक अब अस्पष्ट रुख काम नहीं करेगा और भारत को अपनी नीति को लेकर स्पष्टता दिखानी होगी। बता दें कि भारत ने हाल के महीनों में अमेरिकी दबाव के बाद रूसी तेल आयात में कुछ कटौती जरूर की है, लेकिन इसे पूरी तरह रोका नहीं गया है। इसी बीच सरकार ने रिफाइनरियों से रूसी और अमेरिकी तेल की साप्ताहिक खरीद का ब्योरा भी मांगा है ताकि अमेरिका की चिंताओं को दूर किया जा सके।

गौरतलब है कि भारी टैरिफ के बावजूद नवंबर में भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़ा था, हालांकि मई से नवंबर 2025 के बीच कुल निर्यात में 20 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टैरिफ लागू होने के बाद कम से कम तीन बार बातचीत हो चुकी है, जबकि पिछले महीने भारत के वाणिज्य सचिव ने अमेरिकी व्यापार अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर स्थिति अब भी साफ नहीं हो पाई है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर दबाव और बढ़ सकता है।

उमर खालिद-शरजील को जमानत नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। दरअसल, उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में हैं। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था। उमर जमानत के लिए निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार याचिका लगा चुका है। दिल्ली में फरवरी, 2020 में हिंसा भड़की थी। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं।

*अदालत ने कहा कि अभियोजन और सबूतों, दोनों के लिहाज से उमर खालिद और शरजील इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की केंद्रीय (मुख्य) भूमिका रही है। इन दोनों की हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन यह न तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और न ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है।

*बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी गईं। यह कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा।

*UAPA एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी तुरुप का पत्ता नहीं हो सकती।

*5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती। उन्हें करीब 12 शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा।

11 जनवरी को सोमनाथ पहुंचेंगे पीएम मोदी, 1000 साल पुराने इतिहास पर लिखा भावुक लेख

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार यह पर्व 8 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगा, जिसमें भारत की आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक मूल्यों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन साल भर चलने वाली आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष ओप-एड लेख लिखा है। पीएम ने याद दिलाया कि ठीक 1,000 साल पहले, 1026 ईस्वी में इस पवित्र तीर्थस्थल का पहला बड़ा विध्वंस हुआ था। उन्होंने लिखा, सोमनाथ शब्द सुनते ही मन में गर्व का भाव जागृत होता है। आक्रमणों के सदियों बाद भी यह मंदिर अद्वितीय महिमा के साथ खड़ा है। अपने ब्लॉग पोस्ट में पीएम मोदी ने मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल और के.एम. मुंशी की निर्णायक भूमिका को याद किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख करते हुए लिखा कि 1951 में जब मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं, बल्कि भारत माता की करोड़ों संतानों के अटूट साहस की है। उन्होंने मुंशी की पुस्तक सोमनाथ- द श्राइन इटरनल का हवाला देते हुए बताया कि कैसे महमूद गजनी ने 1025 में कूच किया था और 6 जनवरी 1026 को किलेनुमा मंदिर शहर पर हमला किया था। उन्होंने सोमनाथ को भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

ममता का सीईसी को लेटर, तुरंत रोको एसआईआर

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को एक कड़ा पत्र लिखकर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को तत्काल रोकने की मांग की है। व्यापक अनियमितताओं, प्रक्रियात्मक खामियों और प्रशासनिक अव्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि इस गड़बड़ी से लाखों लोगों के मताधिकार छिन सकते हैं और भारत के लोकतांत्रिक आधार को नुकसान पहुंच सकता है। 3 दिसंबर को लिखे गए इस पत्र ने महत्वपूर्ण चुनावों से पहले टीएमसी सुप्रीमो और चुनाव आयोग के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। बनर्जी के पत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, उन्होंने एसआईआर को अनियोजित, अपर्याप्त तैयारी वाला और तदर्थ विफलता बताया है, जो गंभीर अनियमितताओं, प्रक्रियागत उल्लंघनों और प्रशासनिक चूक से भरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रक्रिया को उचित तैयारी के बिना जल्दबाजी में पूरा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण आईटी सिस्टम, विरोधाभासी दिशानिर्देश और अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित अधिकारी सामने आए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और यह हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर प्रहार करती है। उन्होंने इसे चुनावी निष्पक्षता पर सीधा हमला बताया। उनका कहना है कि यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संशोधन का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन करना है, लेकिन इससे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में वैध मतदाताओं के बाहर होने का खतरा है। बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि एसआईआर को बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ने देने से अपरिवर्तनीय क्षति होगी, योग्य मतदाताओं का बड़े पैमाने पर मताधिकार हनन होगा और लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर सीधा हमला होगा।

पारदर्शिता और निष्पक्षता सवालों के घेरे में

बनर्जी ने विशेष खामियों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें सुनवाई के दौरान बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) को अनुमति न देना शामिल है, जिससे उनके अनुसार निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को ठेस पहुंचती है। उनका दावा है कि अधिकारियों के पास पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है, जिससे इस महत्वपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया में त्रुटियां बढ़ जाती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को उसकी देखरेख में हुई किसी भी अवैध, मनमानी या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है और आईटी खामियों और असंगत निर्देशों को तुरंत ठीक करने की मांग की है।

महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीते तो एमएनएस ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग से किया ये आग्रह

मुंबई। (वेबवार्ता) राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने सोमवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से संपर्क कर ठाणे नगर निगम और राज्य के अन्य नगर निकायों में निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों के चुनाव परिणामों पर रोक लगाने का आग्रह किया। एमएनएस नेता अविनाश जाधव के नेतृत्व में एक पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने एसईसी से मुलाकात कर गहन जांच की मांग की। एमएनएस के ठाणे और पालघर जिला अध्यक्ष जाधव ने कहा कि जांच एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हों। पार्टी ने ठाणे नगर निगम चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। विपक्षी उम्मीदवारों, जिनमें एमएनएस के उम्मीदवार भी शामिल हैं, या तो पैसों का लालच दिया गया या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से उनके नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। इसके परिणामस्वरूप सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे समूह) के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर आघात है। महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। शुक्रवार (2 जनवरी) नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, और इसके समाप्त होते ही महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। महायुति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं। निर्विरोध विजयी हुए महायुति के 68 उम्मीदवारों में से 44 भाजपा से, 22 शिवसेना से और दो एनसीपी से थे। हालांकि, अनियमितताओं के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने शनिवार (3 जनवरी) को जांच के आदेश दिए।

शिवसेना-यूबीटी के आरोप

इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-यूबीटी ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि शिवसेना-यूबीटी और एमएनएस ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए गठबंधन किया है। संजय राउत ने कहा कि मेरे एक मित्र, जो इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं, ने कहा कि (दोपहर 3 बजे के बाद फॉर्म स्वीकार करना) उचित नहीं होगा। उन्हें पालक मंत्री ने एक ऐसे लहजे में कहा जो अनुरोध और धमकी दोनों जैसा लग रहा था, कि उन्हें स्थानीय विधायक की बात सुननी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भाजपा ने बताया करारा तमाचा, कहा- टुकड़े-टुकड़े गैंग के लिए माफी मांगे कांग्रेस

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने का उच्चतम न्यायालय का आदेश कांग्रेस के मुंह पर एक ''करारा तमाचा है। साथ ही पार्टी ने विपक्षी दल से ''टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए माफी मांगने को कहा। भाजपा ने खालिद और इमाम को भारत में विभाजनकारी ताकतों के 'पोस्टर ब्वॉय बताते हुए दावा किया कि उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस का पूरा तंत्र उन्हें ''निर्दोष पीड़ित के रूप में पेश कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में खालिद और इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में हालांकि अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स पर लिखा, ''सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा, ''उच्चतम न्यायालय ने कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोप प्रथम दृष्ट्या सही हैं। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को ''अफजल से लेकर उमर और शरजील तक टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शीर्ष अदालत के फैसले को राहुल गांधी और कांग्रेस के परिवेशी तंत्र के चेहरे पर ''करारा तमाचा बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने ''टुकड़े-टुकड़े के 'पोस्टर ब्वॉय उमर खालिद और शरजील इमाम को निर्दोष पीड़ित के रूप में पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनमत की अदालत और कानून की अदालत में गांधी के ''अर्बन नक्सली पराजित हुए हैं। भंडारी ने कहा, ''क्या कांग्रेस भारत के लिए शत्रुतापूर्ण टुकड़े-टुकड़े ताकतों को पीड़ित के रूप में पेश करने के लिए देश से माफी मांगेगी?

बांग्लादेश में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या, तीन हफ्ते के भीतर पांचवीं वारदात

ढाका। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। एक फैक्टरी मालिक और एक अखबार के कार्यकारी संपादक राणा प्रताप (45) को जशोर जिले में सोमवार शाम सरेआम गोली मार दी गई। घटना मनीरामपुर उपजिला के वार्ड नंबर 17 के कोपालिया बाजार में शाम करीब 5:45 बजे अंजाम दी गई। राणा प्रताप केशवपुर उपजिला के अरुआ गांव निवासी तुषार कांति बैरागी का पुत्र था। चश्मदीदों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बाजार में मौजूद राणा प्रताप पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। उन्हें कई गोलियां लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी के बाद इलाके में डर और अफरातफरी मच गई। वारदात के बाद मनीरामपुर थाने के कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। घटना की पुष्टि करते हुए प्रभारी अधिकारी रजीउल्लाह खान ने कहा कि हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। बैरागी की हत्या बांग्लादेश में हुई ऐसी पांचवीं घटना है। पिछले महीने दक्षिणपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से देश में तनाव का माहौल बना हुआ है। सबसे पहले 18 दिसंबर को मैमनसिंह में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास पर भीड़ ने हमला किया और पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के छह दिन बाद, पांग्शा उपजिला में अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू व्यक्ति की ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने हत्या कर दी। इसके बाद मैमनसिंह में बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी महीने की शुरुआत में 50 वर्षीय हिंदू व्यापारी खोकोन दास पर भी भीड़ ने हमला किया और उन्हें जिंदा जला दिया, जब वह काम से लौट रहे थे। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद दास की शनिवार तीन जनवरी को मौत हो गई।

हिंदुओं की हत्या पर भारत की चिंता

पिछले महीने भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हमले की 2,900 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। 26 दिसंबर को मीडिया को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ चरमपंथियों के लगातार हमले गंभीर चिंता का विषय है।

अब अपनी पार्टी बनाऊंगी... बीआरएस अध्यक्ष चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का बड़ा ऐलान

हैदराबाद।

भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना की एमएलसी के कविता ने आज तेलंगाना विधान परिषद में काफी भावुक भाषण दिया. अपने भाषण के दौरान कविता कई बार रोईं. इसके बाद उन्होंने तेलंगाना के शहीदों के स्मारक पर जाकर बड़ा ऐलान कर दिया. के कविता ने कहा कि वो अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगी. गौरतलब है कि के कविता का अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के साथ काफी तनातनी चल रही थी. के कविता के भाई के टी रामा राव के साथ मतभेद काफी समय से है. अब उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. सदन में कई बार भावुक होते हुए, के कविता ने संपत्ति को लेकर परिवार में चल रही अनबन की अफवाहों पर बात की. भावुक होकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और यहां तक कि मेरे अपने कुछ करीबी लोगों ने भी आरोप लगाया है कि मेरी लड़ाई संपत्ति और जायदाद के लिए है. उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से डरने वाली महिला हूं. उन्होंने कहा कि वह अपने ईश्वर और अपने दोनों बेटों की कसम खाकर कहती हैं, यह धन का मामला नहीं है, यह आत्मसम्मान का मामला है. मैं हमेशा महिलाओं, पिछड़ों और कमजोरों के साथ खड़ी रही हूं और मैं अपनी गरिमा को चुप्पी के बदले नहीं बिकने दूंगी. हालांकि उन्होंने अपने पिता, केसीआर को भगवान के समान बताया, लेकिन उन्होंने अपने विवादास्पद बयान को दोहराते हुए कहा कि वे शैतानों से घिरे हुए हैं और यह भी कहा कि बीआरएस कई मोर्चों पर जनता को निराश कर चुकी है. कविता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही उन्हें बीआरएस के अंदर कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आंतरिक मुद्दों पर सवाल उठाए तो उनके खिलाफ दुश्मनी वाला व्यवहार किया गया. उन्होंने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्टी अयोग्य व्यक्तियों को नेतृत्व करने देती रही, तो भगवान भी बीआरएस को नहीं बचा सकते हैं.